नहीं हो सकता है। इसकी जांच की जाए और निश्चित रूप से उसको रिकॉर्ड पर लिया जाए। इससे पहले भी इस प्रकार की बातें हुई हैं और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों का खर्चा हो गया है और अब दोबारा उनको अप्रैल, 2009 में बुलाया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे उनकी भरपाई करे, इसके लिए पैसा खर्च करे और इसकी पूरी जांच करके हमको बताने की कृपा करे।

### Situation of Female due to Prevailing drought in Uttarakhand

**श्री भगत सिंह कोश्यारी** (उत्तराखंड) : आदरणीय उपसभापति महोदय, उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका और पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड में अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन चार महीनों में एक बूंद भी पानी नहीं आया। इसके दस जिले ऐसे हैं, जहां इस पानी से दस परसेंट भी सिंचाई नहीं होती है अर्थात् पूरा का पूरा वर्षा के पानी पर निर्भर रहता है। सरकारी आंकडे के अनुसार उक्त दस जिलों में इन चार महीनों में सामान्य के मुकाबले शून्य परसेंट वर्षा हुई अर्थात् बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है। इस कारण से वहां हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक ओर तो बारिश नहीं हो रही है, जिससे लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर हमारी केन्द्र सरकार ने, पिछले दो वर्षों के अंदर हमारे उत्तराखंड का पीडीएस में राशन का जो कोटा था, उसको आधा कर दिया है। मैंने इस सदन के अंदर एक प्रश्न पूछा था। उसके लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2005-06 में जहां गेहूं 2,10,000 टन दिया जा रहा था, उसको आज 2007-08 में घटा करके 01,21,000 टन कर दिया गया है। इस प्रकार उत्तराखंड का जो राशन का कोटा था, उसको लगभग आधा कर दिया गया है। यह एक सीमांत प्रदेश है। यह चीन से लगा हुआ प्रदेश है। वहां बहुत संख्या में भूतपूर्व सैनिक रहते हैं और वहां रोजगार के भी कोई साधन नहीं है। मुझे पता लगा है कि वहां की सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है, फोन किया है कि आप ज्ल्दी-से-जल्दी यहां अपना कोई प्रतिनिधिमंडल भेजिए, जो यहां की स्थिति का जांच करके जल्दी-से-जल्दी इसका आकलन करें। आकलन के उपरांत वहां राहत का जो काम शुरू होना चाहिए, उसको जल्दी-से-जल्दी शुरू किया जाना चाहिए।

उपसभापति महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रदेश के एक ओर चीन की सीमा और दूसरी ओर नेपाल की सीमा लगती है। इस प्रदेश में रोजगार के भी कोई साधन नहीं है और आज वहां लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है। आज वहां भुखमरी की स्थिति आ रही है। लोग कहते हैं कि "बुभुक्षितः किम न करोति पापम"। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार वहां के लोगों को भूखा मारने की साजिश कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है, चूंकि वहां विपक्ष की सरकार है, इसलिए वर्तमान में केन्द्र में जो सरकार है, उसके द्वारा जानबूझ कर वहां के लोगों को भूखा मारने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार उसमें प्रभावी कदम उठाए और वहां इस प्रकार की टीम भेजे, जिसके माध्यम से वहां की जनता को तुरंत राहत मिले, अन्यथा वहां असंतोष पैदा हो सकता है। महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

### Request to Expedite Converting the Institute of Technology Bhu into IIT

**डा. मुरली मनोहर जोशी** (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि इस देश में आई.आई.टी. संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उस समय प्रोफेसर एस. के. जोशी की एक कमेटी बनी थी, जिसने कुछ संस्थानों की चिन्हित किया था। उसमें से बनारस हिंदु विश्वविद्यालय का